

बजट 2025: मुख्य घोषणाओं का सरल विश्लेषण

सोने और चाँदी पर आयात शुल्क (Import Duty) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है

- ग्राहकों को आकर्षित करने में चुनौती: बढ़ी हुई कीमतों के कारण व्यापारियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रणनीति बदलनी पड़ सकती है।
- अगर सोने चाँदी में import duty बढ़ती है तोह हमे घरेलु बाज़ार में सोना चाँदी खरीदना मेहेंगा पड़ सकता है.
- रिटेल निवेशक और सराफा व्यापारियों को गिरावट पपर खरीदी करना सुरक्षित रहेगा

Investment & Infrastructure:

- सरकार का 2025-30 के लिए एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लॉन्च होगा।
- राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त लोन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए दिया जाएगा।
- 5 IITs में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।

Income Tax में बड़ी राहत:

- अब ₹12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज पर TDS की लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई।
- किराए पर टैक्स कटौती (TDS) की लिमिट ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई।

Fiscal Deficit में सुधार का लक्ष्य

- वित्त वर्ष FY25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान।
- अगले साल, यानी FY26 में इसे 4.4% तक लाने का लक्ष्य।
- सरकार का फोकस राजस्व बढ़ाने और व्यय को संतुलित करने पर रहेगा।
- कम फिस्कल डेफिसिट से बॉन्ड मार्केट और विदेशी निवेशकों को सकारात्मक संकेत मिलेगा।

विकास को रफ्तार देने के लिए Capex बढ़ाया गया

- FY25 का संशोधित पूंजीगत व्यय (Capex) ₹10.18 लाख करोड़ किया गया।
- बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर), रेलवे, सड़कों और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़ी निवेश योजनाएं।
- हाई कैपेक्स से अर्थव्यवस्था में विकास दर तेज होने की उम्मीद।

- इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, मेटल और कैपिटल गुड्स कंपनियां रहेंगी फोकस में

महत्वपूर्ण बैटरी निर्माण पर कस्टम्स ड्यूटी में छूट

- कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी का कचरा, लीड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) से मुक्त किया जाएगा।
- लेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त वस्तुएं, और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त वस्तुएं को कैपिटल गुड्स की सूची में जोड़ा जाएगा।
- EV बैटरी और मोबाइल बैटरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लिथियम-आयन बैटरी निर्माता
- Vedanta, Hindustan Zinc, Reliance Industries, Tata Steel, Exide Industries, Amara Raja Batteries फोकस में आ सकती हैं।

MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) और स्टार्टअप्स को बढ़ावा:

- स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम को ₹20 करोड़ तक बढ़ाया गया।
- MSMEs के लिए ₹10 लाख का क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा।
- 45% एक्सपोर्ट MSMEs से आता है, इसलिए उनकी ग्रोथ के लिए नया क्लासिफिकेशन लागू होगा।

रोजगार और शिक्षा:

- अटल टिकरिंग लैब्स की संख्या बढ़ाकर 50,000 की जाएगी।
- अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएंगी।
- हर जिले में कैंसर डे-केयर सेंटर बनाए जाएंगे।

कृषि और ग्रामीण विकास:

- युवाओं और महिलाओं को एग्रीकल्चर में लाने के लिए पहली बार अलग बजट।
- फूड प्रोसेसिंग के लिए बिहार में एक बड़ा संस्थान बनाया जाएगा।
- जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया, ताकि 100% कवरेज हो सके।
- कृषि और ग्रामीण विकास से महत्वपूर्ण कंपनियां जैसे UPL Ltd, Patanjali Ayurved, Coromandel International, Rallis India फोकस में हैं।

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष योजना

- तूर, उड़द और मसूर की पैदावार बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा।
- DHAN DHANYA YOJANA के तहत Nafed और NCCF किसानों से दालों की खरीद करेंगे।
- बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिससे मखाना किसानों को समर्थन मिलेगा।

- उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी।
- इससे एग्रीकल्चर सेक्टर और FMCG कंपनियों को फायदा होने की संभावना।

कॉटन उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन

- अतिरिक्त लंबा रेशा (Extra Long Staple) कपास उगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- कपास की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच साल का मिशन शुरू।
- इससे भारत के पारंपरिक वस्त्र उद्योग को मजबूती मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे कॉटन उत्पादक कंपनियां जैसे Nava Bharat Ventures, Kallam Textiles, Raymond Ltd, और Vardhman Textiles फोकस में हैं।

महिलाओं, स्टार्टअप और खिलौना उद्योग के लिए बड़े ऐलान

- 5 लाख महिला उद्यमियों के लिए नई योजना, अगले 5 वर्षों तक टर्म लोन मिलेगा।
- स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना बढ़ाकर ₹20 करोड़ की गई।
- भारत को ग्लोबल टॉप हब बनाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाएगी।
- एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा, खिलौना इंडस्ट्री में नए रोजगार के अवसर।

नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु मिशन:

- 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य।
- एटोमिक एनर्जी एक्ट में संशोधन किया जाएगा।
- ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां जैसे Adani Green Energy, NTPC, Tata Power, और Suzlon Energy फोकस में हैं।

पर्यटन और कनेक्टिविटी:

- टॉप 22 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा ताकि रोजगार बढ़े।
- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बिहार में बनाए जाएंगे।
- UDAN स्कीम को और 120 नए डेस्टिनेशंस तक बढ़ाया जाएगा।
- इससे पर्यटन कंपनियां जैसे Thomas Cook India, MakeMyTrip, EIH Ltd. (Oberoi Hotels) और Indian Hotels Company फोकस में हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग:

- फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी गई।
- LCD/LED के ओपन सेल और कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाकर 5% की गई।

- मोबाइल और EV बैटरी के लिए 35 और 28 नए गुड्स को टैक्स फ्री किया गया।
- इससे **इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनुफैक्चरिंग कंपनियां** जैसे **Dixon Technologies, Tata Elxsi, Samsung India, और V-Guard Industries** फोकस में हैं।

स्टील और शिपबिल्डिंग:

- स्टील आयात पर कस्टम ड्यूटी 10% तक घटाई गई।
- 10 साल तक शिपबिल्डिंग पर BCD छूट जारी रहेगी।
- ₹25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा।
- इससे **स्टील और शिपबिल्डिंग कंपनियां** जैसे **Tata Steel, JSW Steel, Steel Authority of India Ltd. (SAIL), और Cochin Shipyard** फोकस में आ सकती हैं।

राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से निकासी पर कर छूट का प्रस्ताव

- ◆ राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खाता धारकों से की गई निकासी पर कर छूट देने का प्रस्ताव।
- ◆ **इससे** साधारण निवेशकों को लाभ होगा, जो NSS में निवेश करते हैं।
- ◆ साधारण बचत और निवेश क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, और बैंकिंग क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बीमा (Insurance) और वित्तीय सुधार:

- बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 100% तक बढ़ाई गई।
- कंपनियों के विलय के लिए नियमों को आसान बनाया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर KYC वेरिफिकेशन के लिए सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी।
- HDFC Life Insurance Company Ltd.
- ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd.
- SBI Life Insurance Company Ltd.
- Max Life Insurance Company Ltd.
- Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd.
- Reliance Nippon Life Insurance Company Ltd.
- Birla Sun Life Insurance Company Ltd.
- New India Assurance Company Ltd.
- Tata AIG General Insurance Company Ltd.
- Star Health and Allied Insurance Company Ltd... फोकस में आ सकती हैं।

रक्षा बजट 2025-26: 7.6% की बढ़ोतरी, कुल ₹4.91 लाख करोड़

- रक्षा बजट में 7.6% की वृद्धि, कुल बजट ₹4.91 लाख करोड़ तय।
- आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- आधुनिक हथियारों और रक्षा तकनीक के विकास पर जोर।
- सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त फंडिंग।

- इससे रक्षा कंपनियां जैसे Bharat Electronics Ltd. (BEL), Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Larsen & Toubro और Bharat Forge फोकस में हैं।

सारांश

बजट 2025 में मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा राहत मिली है, खासकर टैक्स में। अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज पर TDS लिमिट को ₹1 लाख तक बढ़ा दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास को भी विशेष फोकस मिला है, जैसे कि दालों और कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजनाएं। महिलाओं और स्टार्टअप्स के लिए लोन और क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लॉन्च की गई है।

हालांकि, निवेशकों के लिए ज्यादा खास नहीं था। प्राइवेट कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निवेशकों को इससे तुरंत कोई बड़ा फायदा नहीं होगा।